

प्रषक:

आर० डी० पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

संज्ञा में

महानिबन्धक,
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून दिनांक 28 जनवरी, 2008

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका में सूचित अस्थायी पदों की निरन्तरता/कार्यान्वयि बढ़ाया जाना ।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या-21/XXXVI(1)-टी/2007-10-एक(2)/05 दिनांक 28.02.07 के अनुसार में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए स्वीकृत सभी अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान सभी एवं प्रतिपक्षों के अधीनस्थों के बिना पुनः सुधार के पहले ही स्वयं न कर देने जाए, दिनांक 01-03-06 से 28-02-08 तक बढ़ाए जाने की सहमति स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त न्यायालय के लिए स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त न्यायालय/पदों का सुचारु भूतकाल में शासनादेश संख्या-13-एक(2)/छत्तीस(1)/2005-10-एक(2)/05 दिनांक 29-10-2005 द्वारा किया गया था ।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण धारण करने वाले कर्मचारीयों की सेवा शर्तों सम्बन्धित शर्तों की सेवा नियमावली से अवधारित होगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 की लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-अधीनस्थ-105-निर्देश और सेवान्वय न्यायालय-03-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-00" के नाम से आला जायेगा ।

4- यह आदेश जिला विभाग के कार्यालय ज्ञान संख्या-ए-1-1270/78-दस दिनांक 20 जुलाई, 1988 संबंधित कार्यालय ज्ञान संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92 दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधित्वित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं ।

स्वस्ती,

(आर० डी० पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 25/xxxvi(1)/2008-10 एक(2)-05/2008 तददिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड माजरा, देहरादून ।
- 2- समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
- 3- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड ।
- 4- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एनआईसी/गैटई कार्ड ।

जायेंगे
(अलीक कुमार ठगो)
अपर सचिव ।